Mr. Chairman: One hon. Member, Shri Subodh Hansda, having amendment Nos. 16, 17 and 18 in his name is absent.

His amendments will be deemed to be negatived.

Amendments Nos. 16 to 18 were deemed to have been negatived.

Mr. Chairman: I shall now put the main motion to vote.

The question is:

"That this House takes note of the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1958-59, laid on the Table of the House on the 22nd December, 1959."

The motion was adopted.

16.33 hrs.

CORRECTION TO RESULT OF DIVISION

Mr. Chairman: I am authorised by the Speaker to make the following announcement. I have to inform the House that there were errors in the announcement of the result of the division held on the 19th August, 1960 on the Resolution moved by Shri Ram Krishan Gupta in regard to Ceiling on income. The House has already taken a decision and these errors have absolutely no effect on it. However, I consider that the correct position should be on record.

On a check-up of the photograph and the proceedings it now transpires that the correct result should be 'Ayes' 23; 'Noes' 81 instead of 'Ayes' 24; 'Noes' 80, as announced yesterday.

16.34 hrs.

AGRICULTURAL PRODUCE (GRADING AND MARKING) AMENDMENT BILL

Mr. Chairman: The House will now take up the consideration of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Amendment Bill.

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This is an amending Bill to amend the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act 937, which has already been passed by the Rajya Sabha. It is a simple one. All that we seek to do is to make it applicable by this amendment to the State of Jammu and Kashmir. It used to be the practice till some time ago to make these legislations not applicable to the State of Jammu and Kashmir. But now that it is part and parcel of India we want to extend it to the State of Jammu and Kashmir and this Bill is brought with that intention.

I do not know if hon. Members would like me to speak on the importance of the original Act which was passed in 1937, or to dwell on the importance of grading of agricultural produce. I think it is self-evident, especially for anybody who knows about grading of agricultural produce both inside the country and outside that grading is extremely important.

If there is no grading and no proper criteria of the quality laid down then it is the grower who suffers because we will then have to rely only on our physical inspection of goods which generally leads to the grower suffering a lot of loss on account of it. So everybody has realised the importance of grading of agricultural produce and in 1937 this Act was put on the statute book.

We have also, through the Directorate of Marketing, tried to enforce the provisions and make them applicable to various commodities. There are two parts of it.

Shri Braj Raj Singh: Could I seek a clarification? Is the speech that the hon. Minister is making within the scope of the Bill? The scope is only this, namely, that—

> "In sub-section (2) of section 1 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, the words 'except the State of Jammu and Kashmir' shall be omitted."

Mr. Chairman: That is what the hon. Minister said. He is only explaining, if the House wants it.

Dr. P. S. Deshmukh: If the House does not want, I am not keen on taking the time of the House. I will be quite prepared merely to move the consideration of the Bill without any elaboration of what we have done.

Shri Nagi Reddy (Anantapur): I think he can continue.

Shri Achar (Mangalore): We should have the main facts.

Dr. P. S. Deshmukh: The motion may be put to the House.

Mr. Chairman: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): Mr. Chairman, Sir, at the very beginning I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this amending Bill to the original Act. We are very happy to learn that the original Act regarding and marketing of agricultural produce is being extended to the State of Jammu and Kashmir. I would only like to say a few words.

After going through the original Act, I feel that it is necessary that the original Act should also be reviewed now considering the fact that after 1937 we have made a good deal of progress in the agricultural field and everyday we are emphasising the need to increase agricultural production. At the same time I feel that marketing and grading of all agricultural produce is also very important. Keeping this fact in view I would suggest that special attention should always be paid to the marketing and grading of fruits, dairy products and vegetables.

In the end I would again congratulate the hon. Minister for bringing this amendment to the Bill. As in the past the present Government of Jammu and Kashmir under the leadership of Bakshi Ghulam Mohammed have always been bringing legislation inside the State and are also requesting the Central Government to extend the beneficial and the required legislation to the State of Jammu and Kashmir. In this case also the State Government had agreed.

With these words I support the Bill.

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन इसी अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बडी खेदजनक बात है कि जब भी किसी वर्तमान कानून को कश्मीर राज्य में लागू करना होता है तो उस के लिए हमें इस सदन में आना पडता है ।

मुझे दुःख है कि मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते हुए जो भाषण दिया और उस से जो उन्होंने कह दिया वह वास्तविकता के खिलाफ है कि कुछ समय पहले तक हमें यह देखना पडा कि यह कानून

लागू नहीं होता कश्मीर और जमू में लेकिन स्थिति आज यह है कि जिन कानूनों को कश्मीर की विधान सभा मंजूर न कर ले अपने आप उन सब कानूनों को हमें यह लिखना पडेगा कि यह जम्मू और कश्मीर स्टेट में लागू नहीं होगा। अब इस कानून के बारे में यह है कि चूंकि कश्मीर की सरकार ने इसे मंजुर कर लिया हैं इसलिए यह वहां लागु किया जा रहा है। इसलिए नहीं लागु किया जा रहा है कि मिनिस्टर साहब चाहते हैं या यह सदन चाहता है। मैं यह कहना चाहता हुं कि अब समय आ गया है कि जब कश्मीर सरकार से मिल कर यह प्रयत्न किया जाय कि जितने कानुन हिन्दुस्तान में है वह सारे के सारे कानुन काश्मीर में भी लागु हों और यह जरूरी भी न पडे कि जो भी पुराना कानुन हो और उसको कश्मीर में लागु करना हो तो इस सदन में उसके लिए आना पडे और विशेष अधिकार लेना पडे। मैं समझता हूं कि इस बिल का सिर्फ यही उद्देश्य है और इसी भावना से इस को लेना चाहिये।

जहां तक कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ग्रेडिंग और मार्किंग का सवाल है, मैं नहीं समझता कि खुद मिनिस्टर साहब भी उस से संतुष्ट हैं या नहीं कि उस से हिन्दुस्तान के काश्तकारों और किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है। अगर हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर महोदय इस सदन में एक वार्षिक विवरण रखा करें कि सारे हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों में इस से लाभ हुआ है और इस कानून पर अमल हो रहा है। अब तक सम्भवतः इस तरह की बात नहीं हुई है। यदि मिनिस्टर साहब समझते हैं कि इस कानून से फ़ायदा हुआ है किसानों का, तो उन्हें एक विवरण ज़रूर सदन में हर साल रखना चाहिये, जिस से सदस्यों और इस मुल्क को मालूम हो सके कि किस तरह इस कानून से काश्तकारों का फ़ायदा हो रहा है।

अन्त में मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि इस बिल को पास करने के वक्त पर हमें विचार करना चाहिये और हिन्दुस्तान की सरकार को काश्मीर की सरकार से सलाह-मश्विरा करना चाहिये और उन से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि वह उन सारे कानूनों को, जोकि हिन्दुस्तान में लागू हैं, पूर्ण रूप से काश्मीर में लागूकर लें। काश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता। काश्मीर के लोग भी यही कहते हैं और वह हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन उस के होते हुए भी यह दिक्कत रहती है कि इस देश के कुछ कानून वहां पर लागू नहीं होते हैं, जब तक कि काश्मीर की असेम्बली उन को स्वीकार न कर ले। मैं आशा करता हूं कि इस तरह का कोई संशोधन काश्मीर असेम्बली करेगी, जिस से जो कानून हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में लागू हैं, वहां भी लागू हो जायें।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब सदर, जो तहरीक वज़ीर साहब ने इस ऐवान में पेश की है, मैं उस की ताईद करता हूं। मुझे अफ़सोस है कि मेरे दोस्त ने, जो अभी मुखालिफ़ बैंचों से बोले हैं, एक ग़लत वक्त पर सही राय का इज़हार किया। इस वक्त मसला यह नहीं था कि कांस्टीच्यूशन में उन की मरज़ी और पसन्द के मुताबिक तरमीम की जाये। मसला यह था कि जिस बिल का अमेंडमेंट लाया गया है, उस के बारे में वह कुछ फ़रमाते। बहरहाल जहां तक उस मसले का सवाल है, जिस का ज़िक्र मेरे दोस्त ने किया है, मैं इस ऐवान को एक काश्मीरी की हैसियत से यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तान के आईन के उतने ही पाबन्द हैं, जितने कि और लोग हैं। अब वह मसला कैसे तय होगा, यह कांस्टीच्यूशन की बात है।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, मैं यकीनन यह समझता हूं कि इस से रियासत

[श्री अ० मु० तारिक]

काश्मीर के किसानों को और उन लोगों को एक बड़ी हद तक फ़ायदा होगा, जिन्हें बड़े बड़े बिजिनेसमैन एक्सप्लायट करते थे । इस में कोई शक नहीं कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है, लेकिन हम और जगहों के मुकाबले में बेहतरीन फ्रूट्स पैदा करते हैं । उन की ग्रेडिंग से यकीनन वहां के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और वहां के लोगों को मौका मिल जायगा कि मौजूदा ज़माने में, मौजूदा दुनिया में जिस साइंटिफिक तरीके से ग्रेडिंग की जाती है, या मार्किंग की जाती है, उस के ज़रिये वे हिन्दुस्तान की दूसरी रियासतों के मुकाबले में काम कर सकें और उस से हमारे मुल्क की माली हालत में इज़ाफ़ा होगा ।

इस बिल को लाने के लिये मैं हुकूमत और वज़ारत एग्रीकल्चर को मुबारकबाद देता हूं ।

[شری ع - م - طارق (جموں تتھا کشمیر) - جناب صدر - جو تحریک وزیر صاحب نے اس ایوان میں پیش کی ہے میں اسکی تائید کرتا ہوں— مجھے افسوس ہے کہ میرے دوست نے جو ابھی مخالف بنچوں سے بولے ہیں ایک غلط وقت پر صحیح رائے کا اظہار کیا ہے - اس وقت مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کنسٹیچیوشن میں انکی مرضی اور پسند کے مطابق ترمیم کی جائے - مسئلہ یہ تھا کہ جس بل کا امینڈمینٹ لایا گیا ہے اسکے بارے میں وہ کچھ فرماتے - بہر حال جہاں تک اس مسئلے کا سوال ہے جس کا ذکر میرے دوست نے کیا ہے میں اس ایوان کو ایک کشمیری کی حیثیت سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے آئین کے اندر ہی پابند ہیں جتنے کہ اور لوگ ہیں - اب یہ مسئلہ کیسے طے ہوگا یہ کانسٹیچیوشن کی بات ہے -

جہاں تک اس ترمیم کا تعلق ہے میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ریاست کشمیر کے کسانوں کو اور ان لوگوں کو ایک بڑی حد تک فائدہ ہوگا جنہیں بڑے بڑے بزنیسمین ایکسپلائٹ کرتے تھے - اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے لیکن ہم اور جگہوں کے مقابلے میں بہترین فروٹس پیدا کرتے ہیں - ان کی گریڈنگ سے یقیناً وہاں کے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور وہاں کے لوگوں کو موقعہ مل جائیگا کہ موجودہ زمانے میں موجودہ دنیا میں جس سائنٹیفک طریقے سے گریڈنگ کی جاتی ہے یا مارکنگ کی جاتی ہے اسکے ذریعے سے ہندوستان کی دوسری ریاستوں کے مقابلے میں کام کر سکیں اور اس سے ہمارے ملک کی مالی حالت میں اضافہ ہوگا -

اس بل کو لانے کے لئے میں حکومت اور وزارت ایگریکلچر کو مبارکباد دیتا ہوں -]

श्री पद्म देव (चम्बा) : सभापति जी, काश्मीर सरकार को इस बात की दुहाई कि उस ने इस अधिनियम को अपने यहां

लागू किया है । जब से देश आज़ाद हुआ है, सरकार ने इस बात का बड़ा भारी प्रयत्न किया है कि कृषक लोगों को ज्यादा से ज्यादा साधन-सम्पन्न किया जाये, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उपज कर सकें । चुनांचे फलों में और खेती बाड़ी की दूसरी चीजों में किसानों ने बहुत ही उन्नति की है, लेकिन उस उन्नति के साथ साथ उन को इस बात का अभी तक पता नहीं कि पैदा करने के बाद उन की चीज़ कहां जायगी और कहां ज्यादा पैसा उन को प्राप्त हो सकेगा । जो लोग आज तक एक्सप्लायट करते रहे हैं इन सीधे सादे, धूप में तपने वाले और सरदी में ठिठुरने वाले लोगों को, वे हमेशा ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं और विशेष तौर पर नगरों में ऐसी बातों के लिये शोर-शराबा, हड़तालें और दूसरे प्रदर्शन होते रहते हैं कि रूई की कीमत बढ़ गई, या शूगर केन की कीमत बढ़ गई और इस बात के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि इस किस्म की चीज़ों के लिये किसी तरह का कोई प्रबन्ध न हो । यह ठीक हैं कि सरकार किसानों के लिए साधन जुटाती है और ज्यादा उपज करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि जब कि वह गद्दी पर बैठने वाले कर्मकारों की चीज़ों के बेचने का प्रबन्ध करती हैं, उस के लिए एम्पोरियम खोलती है, तो कोई वजह नहीं है कि जो खेत में तपने वाला किसान है और जो देश की वास्तविक ज़रूरत को पूरा करने वाला है, उस की चीज के लिए वह मार्केट न पैदा करे । मैं जानता हूं कि ये पहाड़ी इलाके हैं और आलू, सेब और इस किस्म की चीज़ें उपजाते हैं, लेकिन जिस तरह से इन के ऊपर लूट-मार होती है मंडियों में, वह हर एक आदमी जान नहीं सकता, जब तक कि वह वहां अपनी आखों से यह सब न देखे । इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि किसान को यह बताया जाये, समझाया जाये और इस बात का प्रबन्ध किया जाये कि उस की चीज़ें किस तरह ग्रेड की जा सकती हैं, क्योंकि ग्रेडिंग करने से उनको अधिक पैसा मिलेगा और उस के पश्चात् उन चीज़ों के लिए मार्केट ढूंढे कि किन मंडियों में उन को ज्यादा पैसा मिलता है । जो लोग लोगों के लिए फल, अनाज, खांड और रुई पैदा करने वाले हैं, अगर इस तरीके से उन के लिए, ठीक तरह का प्रबन्ध नहीं होगा, अगर यह अंग कमज़ोर रहेगा, तो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकेगा । अगर हम केवल विदेश की चीज़ों पर ही आधारित रहे, तो कभी भी देश में लड़ाई हो जाये, झगड़ा हो जाये, तो दुश्मन को हमारे लिये एटम बम की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हमारी सप्लाई बन्द कर के वे हम को वैसे ही मार सकते हैं ।

इसलिए हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और जैसे यह काश्मीर में लागू हुआ है, सर्वत्र इस किस्म के नियम बनने चाहिए, ताकि किसान की पूरी सहायता हो सके ।

श्री ब्रजराज सिंह : सर्वत्र तो पहले ही है ।

श्रीमती कृष्णा महता (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति जी, मैं कृषि उत्पादन (श्रेणीकरण तथा चिह्न लगाना) संशोधन बिल का स्वागत करती हूं । यह संशोधन ला कर केन्द्रीय सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है । साथ ही मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने भी इस को अपने राज्य में लागू करने की इच्छा प्रकट कर के एक बहुत बड़ा काम किया है । मुझे आशा है कि जम्मू-काश्मीर की जनता इस का पूरा स्वागत करेगी । सम्वत् १९३७ में यह अधिनियम भारत में लागू हुआ था । आज २३ वर्ष के बाद काश्मीर में भी यह लागू होगा । मैं तो कहती हूं कि बहुत पहले ही यह आ जाता और इस से काश्मीर की जनता और किसानों को बहुत फ़ायदा होता ।

काश्मीर बहुत सी चीज़ों का विक्रय कर सकता है और केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

वह उस के लिए पूरी सहायता करे । वहां कुछ बड़े बड़े कारखाने होने चाहिए, क्योंकि मैं सोचती हूं कि वहां पर ऊन, पशमीना वग़ैरह जो कच्चा माल है, उस का माल वहीं बनना चाहिए । अगर कहीं यह कच्चा माल बाहर आ गया, तो इस से बड़ी ही दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि आज भी वहां के मजदूरों को ऊन और पशमीने से काफ़ी फ़ायदा होता है । अगर वहां कारखानों की कमी रही, तो वे कह सकते हैं कि वहां से कच्चा माल बाहर जा सकता है । इस तरफ़ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

वहां पर शिल्प-कला की बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं तथा और भी बहुत सी चीजें हैं, जो संसार भर में विख्यात हैं । हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार को उस के लिए भी ऐसा पग उठाना चाहिए, जिस से कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वहां हो और उस के बाहर विक्रय करने का प्रबन्ध हो । इस के अलावा वहां की कृषि में भी बहुत सी चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे ज़ाफ़रान है, जो संसार भर में मशहूर है । हमारे यहां फल भी हैं, लेकिन उन के लिये हमारे यहां कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं, उनके रखने का ठीक प्रबन्ध नहीं है, उन को विक्रय करने का प्रबन्ध नहीं है कि वह कैसे बाहर भेजा जाये । अगर केन्द्रीय सरकार इस तरफ ध्यान दे और इन चीज़ों को बाहर भिजवाने और ज्यादा से ज्यादा विक्रय करने की व्यवस्था करे, तो मुझे पूरी आशा है कि काश्मीर इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, जिस तरह कि वह दूसरे हर पहलू से आगे बढ़ रहा है । आज काश्मीर वह काश्मीर नहीं है, जो नौ दस वर्ष पहले था । आज वहां की जनता अपना गरीबी का चोला बदल रही है और दिन-प्रति-दिन आगे बढ़ती जा रही है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधक विधेयक का अनुमोदन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं ।

Shri Ansar Harvani (Fatehpur): This Bill has not got two aspects. One is the political aspect, and the other is the economic aspect. As far as the political aspect is concerned, I congratulate the hon. Minister on having brought forward this Bill, but I hope and trust that he will convey the message to his colleagues in the Cabinet that the time has come when they should devise some formula whereby in future, no Bill should be brought forward in this House just to provide that the words 'except Jammu and Kashmir" should be omitted.

We know very well that Kashmir today has become an integral part of India. Kashmir is as much a part of India as Kerala or U.P. or Bihar...

Shri D. C. Sharma: Or Punjab also.

Shri Ansar Harvani: ....or the present Punjab.

Shri A. M. Tariq: What about future Punjab?

Shri Ansar Harvani: I hope and trust that in future there will be no occasion to bring forward this sort of measure.

Now, I come to the other aspect of the Bill. This Act was passed in 1937. Since then, much has happened in India in the field of agriculture, in the field of animal husbandry, and in the field of poultry, and under the guidance of our hon. Minister, we have made tremendous progress, though the production has not very much increased. Still, we feel that the outdated Act should be modified and I hope that a Bill will soon be brought forward in this House, which would make the measure more effective.

We know very well that in spite of this Act, there is adulteration throughout the whole country. We know very well that in spite of this Act, advantage is being taken by the officials in the States as well as at the

Centre in the Agriculture Ministry and they misuse the Act and adulterated stuff is passed on sometimes as good stuff. Therefore, stricter measures should be taken, and stricter punishment should be meted in such cases.

I hope and trust that the hon. Minister will bring forward an amending Bill in the very future which will make this Act more effective and more useful for this country.

With these words, I congratulate the hon. Minister on his having brought forward this Bill.

Dr. P. S. Deshmukh: There are a few points which hon. Members have made, but on the whole, I am very grateful to them for having welcomed this measure. I was rather surprised that my hon. friend opposite, while objecting to my making a reference to the substantive enactment himself not only went against it but made certain observations which were, I think, not very necessary while passing a Bill like this, although, the motive or the intention behind it was welcome to me; hon. Members on this side of the House have also made some references to it.

It has been stated that it should not be necessary for us to bring forward in respect of every Act, an amending Bill like this, and since Kashmir is an integral part of India, *ipso factofi* every Act should more or less apply to it. I fully sympathise with that sentiment expresed by the hon. Members, and I am sure due notice will be taken of it by Government.

My hon. friend Shri Inder J. Malhotra wanted to know whether from the time was passed this measure, we had been making progress or not. I am in a position to tell him that both the scope and the commodities coming under the Act are being expanded from year to year. I am not absolutely satisfied with the progress, but we are trying to do the best in the circumstances, for, in regard to the addition of any particular commodity, we have to consider various aspects of it, and especially the views of the Ministry of Commerce and Industry.

While moving the original motion, I thought I would not be taking a very long time, but since the point has been raised, I might say that there are two aspects of the Bill; one is the internal and the other is the external. The internal aspect is in respect of commodities to be graded which are consumed largely in the country; the external aspect is in respect of those commodities which have an export market. In the case of commodities which we sell outside India, we make is compulsory that they should be graded. In the case of commodities sold in the country, it is voluntary. So, we are trying to expand the scope of both the voluntary grading as well as compulsory grading from year to year. We have not only added new commodities but have been able to grade on a larger scale. I am happy to say that the *Agmark* is recognised as a reliable seal and a reliable standard for judging the quality of the material not only in India but outside wherever and I fully agree with my hon. friends that we should do all we can to extend the scope of this legislation to as many more commodities as possible and do it on a still larger scale so that the adulteration and the losses which the growers suffer would not be there.

My hon. friend Shri Padam Dev has referred to the importance of this from the point of view of the cultivators; and I am fully conscious of it; so is my Ministry. We, will therefore, take into account all the observations that have been made by hon. Members. We are ourselves anxious as I said in the beginning. Without grading, the best material would be sold at the worst price possible; for want of grading the middlemen and the traders also have to have a

[Shri Ansar Harvani]

larger margin of profit in case the commodity does not answer the specifications and the quality required by the purchasers. In various other ways also, it causes a lot of harm and loss to the agriculturists.

In Kashmir itself there are commodities to which it will be made voluntarily applicable such as rice and fruits and vegetables, etc. But there are other commodities also which are exported out of Jammu and Kashmir. Therefore, this Act will be compulsorily applied to them. I am glad that the Jammu and Kashmir Government came forward with this suggestion. We were very happy to agree with it and bring forward this Bill; and I have no doubt that this legislation will confer a lot of benefit on the producers in Jammu and Kashmir.

Sir, I move.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill further to amend the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: We will now take up clause by clause consideration. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill.".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 1, Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

Dr. P. S. Deshmukh: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16:59 hrs.

EVACUEE INTEREST (SEPARATION) AMENDMENT BILL

Mr. Chairman: Now, we take up the next item, the Bill to amend the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951.

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mehr Chand Khanna): Sir, I beg to move—

"That the Bill to amend the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

While making this motion I have no intention to make a very long speech. The simple reason is that this Bill is rather of a non-controversial nature; and, secondly, as far as know, no amendments have been tabled to this Bill at all. So, in a way, it is accepted that there is no controversial point involved in this Bill at all.

Before I come to the amendment that I am bringing forward before this House I think it may be desirable if I give some background of the parent Act that was passed about 9 years ago. We can then appreciate the impilcations and the necessity of that Act and my task in bringing the amendment today will become very easy or much easier.